कभी बनाएं राष्ट्रीय एकता की सरकार

संकीर्ण राजनीतिक टकराव दूरगामी महत्व के मुद्दों पर कोई चर्चा तक नहीं होने दे रहे हैं

भारत डोगरा

संसदीय लोकतंत्र का एक मुख्य तौर-तरीका आम तौर पर यही माना जाता है कि एक सत्ता पक्ष होगा और दूसरा विपक्ष होगा। हाल के समय में भारत में चूंकि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना राष्ट्रीय स्तर पर कम होती गई है, अतः सत्ता पक्ष प्रायः अनेक दलों के आपसी गठबंधन से ही बन पाता है। इसके लिए कई बार ऐसे गठबंधन एक साझा कार्यक्रम भी तैयार करते हैं। अब इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या इससे एक कदम आगे जाकर राष्ट्रीय एकता की ऐसी साझा सरकार नहीं बन सकती जिसमें लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का कुछ प्रतिनिधित्व रहे? पहली नजर में तो यह सुझाव-अव्यावहारिक लगता है, पर यदि ऐसी सरकार की जरूरत गहराई से समझी जाए तो फिर व्यावहारिक समाधान भी निकल सकते हैं।

कैसे बचें देसी नस्लें

राष्ट्रीय एकता की साझा सरकार की जरूरत मुख्यतः इसलिए है कि कुछ महत्तवपूर्ण मुद्दों पर देश में व्यापक सहमति बनना व्यापक राष्ट्रीय हित में है। सत्तापक्ष और विपक्ष में बंटे संसदीय लोकतंत्र का अर्थ यह नही है कि हर मुद्दे पर, हर बात पर आपस में लड़ा जाए या हमेशा एक-दूसरे के प्रति विरोध व संदेह बना रहे। पर हाल के वर्षो में न केवल इस प्रवृति ने जोर पकड़ा है बल्कि इस विरोध को जताने के तौर-तरीके भी नम्रता से दूर जा रहे हैं। कई बार बेहद अनावश्यक मुद्दों पर और अनुचित शब्दों के चुनाव पर बड़े तीखे वाद-विवाद हो जाते है, जबकि व्यापक राष्ट्रीय हित के मुद्दे बुरी तरह उपेक्षित पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए देश के परंपरागत बीजों को बचाने के मुद्दे पर चर्चा की नौबत ही नही आती, जबकि यह अमूल्य संपदा हमारे खेतों से बड़ी तेजी से लुप्त हो रही है। जर्मपलास्म बैंकों में इन बीजो का नमूना रख देने से ये नहीं बचेंगे। इन्हें तो खेतों में उगाना होगा और इनसे जुड़े परंपरागत ज्ञान को बचाना होगा। देश के पशुधन और देसी नस्लों की गिरावट रोकना और उनकी रक्षा के कदम उठाना भी जरूरी है।

पहले माना जाता था कि संघ परिवार ऐसी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सचेत है, पर हकीकत ये देखी गई कि ऐसे बुनियादी मुद्दों को लेकर देश की समूची राजनीतिक मुख्यधारा का रवैया एक सा है।

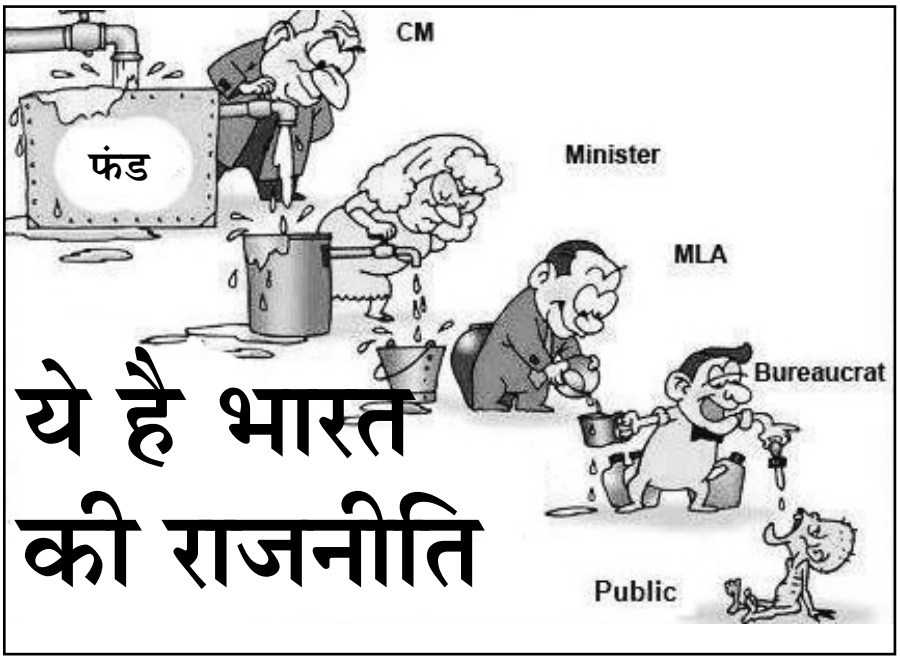

अतः दीर्धकालीन हितों और स्थायी क्षति रोकने के मुद्दों पर व्यापक राष्ट्रीय एकात की साझा सरकार एक अनिवार्यता बनती जा रही है। इसी तरह एक महत्तवपूर्ण पक्ष है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और धर्म, जाति, क्षेत्र आदि पर आधारित हिंसा को रोकना। सभी राजनीतिक दल बाहरी तौर पर इस उद्देश्य को स्वीकार करते है पर कड़वी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि उनमें से ज्यादातर स्वयं ऐसी हिंसा को अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए बढ़ावा देते हैं। इस संभावना को न्यूनतम करने में भी साझा सरकार से सहायता मिलेगी। विदेशी नीति के मुद्दों पर, खासकर चीन तथा पाकिस्तान से संबधों के मुद्दे पर भी कई बार आम सहमति की जरूरत होती है। यदि कोई सरकार तनाव व हिंसा कम करने की योजना बनाए, पर उसके ऐसे हर प्रयास को संदेह की ही नजर से देखा जाए और विपक्ष ऐसे हर प्रयास को उसकी कमजोरी बताकर लोगों को भड़काए तो ऐसे प्रयास कभी आगे नही बढ़ पाएंगे। ऐसे प्रयासों की प्रगति में भी राष्ट्रीय एकता की साझा सरकार से सहायता मिलेगी।

यदि एक बार साझा सरकार की जरूरत को स्वीकार कर लिया जाए तो अगला सवाल यह है कि इसकी व्यवहारिक राह क्या हो? एक राह यह हो सकती है कि जिस दल को सबसे अधिक संसदीय सीटें प्राप्त हों वह मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी दलों के अतिरिक्त विपक्ष के दलों को भी शामिल करे और विपक्षी दल भी इसे सही भावना से स्वीकार करें। कौन सा मंत्रालय किसे देना है, यह अधिकार प्रधानमंत्री का ही रहेगा और इसके बारे में किसी भी दल को विवाद नहीं खड़े करने चाहिए। यह भी मानकर चलना चाहए कि जिस दल को सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए हैं, असे व उसके सहयोगी दलों को ही मंत्रिमंडल में अधिक स्थान मिलेगा।

विरोध की स्वतंत्रता

हो सकता है, विपक्षी दलों को लगे कि उन्हें बहुत कम स्थान मिलता है। इसके बावजुद उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सरकारी में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ताकि इस प्रयोग को आजमाने व इसे सफल बनाने का एक प्रयास तो हो सके। राष्ट्रीय एकात की साझा सरकार में शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि जहां जरूरी हो वहा विपक्ष सरकार का विरोध नही करेगा। इस तरह के विरोध की उसकी स्वतंत्रता पहले की ही तरह बनी रहेगी। अलबत्ता